

संपादकीय

कहां जानी महामहिम की अहमियत

इस बार हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह बात कही, तो जिक्र बदल गया, बरना यह तथ्यों से भरा अनुभव है कि महामहिम दलाईलामा की उपस्थिति के कारण धर्मशाला शहर क्या एक अंतरराष्ट्रीय डेरिटेनेशन बन गया है। आश्वय यह कि हिमाचल के मंच सिफक कह देने के लिए कह देते हैं, वरन् दलाईलामा के संदर्भ में हमारे पर्यटन की तासीर बदल जाती। दूर जाने की जरूरत नहीं, कुछ दशक पहले जब महामहिम को विश्व शांति पुरस्कार मिला, तो उनकी आभा में एक हिमालय उत्सव का श्रीगणेश मकलोडगंज में हुआ। हैरानी यह कि अब विधायकों के महिमामंडन में ऐसी जगह ऐसे समारोह शिष्ठ हो गए, जहां सिर्फ पंजाबी गायकों के बागांचे में लाखों खुच होते हैं। धर्मशाला के जिस वैभव का जिक्र महादेव उपमुख्यमंत्री कर रहे हैं, वहां हिमालय उत्सव ढूढ़े नहीं मिलता। जिस शहर में अंतरराष्ट्रीय हस्तियां पूजनीय दलाईलामा से मिलने आती हैं तभी उनकी पहली घेंट सदाबहार गंगां, ट्रैफिक जाम, अव्यवस्था, अतिक्रमण, स्टूट-सट्टू और प्रकृति के ढांचे से होती है। राजनीति ने बस रेस्टेंड की बीओटी को मुदाधर बना दिया, जहां दफन हैं मोटे और लंबे देवदार के पेड़। पार्किंग के नाम पर होटल खड़ा कर देने वालों को सियासी पगाह भी जगब कि सुप्रीम कोर्ट की हड्डें अब इसी अंतरराष्ट्रीय शहर में लगती हैं। ऐसे गुनाह से तो बेबाई भी अच्छी, लेकिन यहां तो वर्षों से डल झील की गाद ने सारी बस्ती उड़ा दी। एक जलप्रपात था, उसके पानी को इतना खींच लिया कि यह आलम अब लुप्तप्राय होने के कागार पर है। जरा बताएं महामहिम के पक्ष में उन्हीं बातें करने वाले हिमाचली नेताओं और सत्ता पक्ष के अहम किरदारों ने अंतरराष्ट्रीय छवि के मुताबिक उनके गृह शहर में किया था। पर्यटन विभाग ने अपनी बैंशकीमती 65 कनाल भूमि के ऐसे टुकड़े किए कि बलब हाउस भी सराय में लाला लगत है। दोषी स्थानीय लोग और होटल व्यवसायी भी कम नहीं हैं। यहां बन खुम पर नागरिक अधिकार चलता है। ऊंची इमारतों के बहुत नीचे इनसानों का काढ़ कितना बौना हो सकता है, यह हम पर्यटन की बाबूरों में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था भी तो चाहिए। दलाईलामा का 90वा जन्मदिन मनाने आए एक लाख से अधिक लोगों से ही पछ लें कि क्या यहां किसी अंतरराष्ट्रीय शहर की पूँछ भी दिखाई देती है। दरअसल हमारी योजनाएं सत्ता के किरदार में पूँजी जाती हैं, इसलिए पर्यटन इकाइयों के कबाड़खानों में कई नेता गुनाहगर हैं। सिर्फ एडीबी का पैसा पर्यटन को सर्वांगीन, ब्रॉक्स सर्वांग जैसे दिमाचल को बचाने की दुरुस्ती चाहिए। इसी धर्मशाला में तमाम टैक्सियों में घूमकर, रेस्टरा में खाकर और सुकून के पल तलाशकर मालूम हो जाएगा कि हम तो राष्ट्रीय स्तर का महत्व भी नहीं जानते। इससे पहले किसी ने कहा कि पर्यटन के ब्रॉक्स होगे दलाईलामा। हैमत तो कांगड़ा के एयरपोर्ट को महामहिम दलाईलामा के नाम पर अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर बनाएं। हकीकत यह है कि भारत के लोकतांत्रिक व महामहिम गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का पुजारी वर्षों से मकलोडगंज की वादियों से तप कर विश्व को यहां आमत्रित कर रहा है, लेकिन हम इस महत्व को न पर्यटन और न ही संस्कृति में समझे। अगर धर्मशाला-लाहौल-किन्नौर तक एक बोद्ध सकिंट भी बना देवे, तो कालचक्र जैसे समारोहों की अधोसंचन जांगिनगर जैसे मध्य स्थल पर उभर आती। केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला के अहमियत दी होती, तो यहां एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का विश्व विख्यात केंद्र अब तक विकसित हो चुका होता। दलाईलामा के सम्मान में विश्व शांति स्थल विकसित करके यहां वैश्वक स्थान स्थापित किया जा सकता था।

अतार्किक विकल्प: चीनी आपूर्ति वर्चस्व औद्योगिक नीति को पुनर्स्थापित करने की दरकार

पहले दुर्लभ खनियों के नियात पर प्रतिबंध लगाकर भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नियातियों को मुश्किल में डाला गया था। अब चीन ने विशेष उभरकों पर रोक लगा दी है। भारत में आने वाली जर्मनी की सुरंग-बोरिंग मशीन कथित तौर पर चीन में फंसी हुई है जिसके लिए नियात मंजुरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। अब इससे ज्यादा क्या होगा? भारत, दबाओं का एक बड़ा नियात देश है और अपनी प्रमुख दवा सामग्री का 80 फीसदी चीन से आयात करता है।

सबल यह है कि अगर इस पर भी रोक लग गई तब क्या होगा? चीन को भारत से किसी भी महत्वपूर्ण चीज का आयात करने की जरूरत नहीं है जबकि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न दृस्तों को चलाने के लिए हर साल चीन से 115 डॉलर अरब के सामान की जरूरत होती है।

अर्थव्यवस्था में राष्ट्र-नियमण के लिए विनिर्माण को कम महत्वपूर्ण मानने वाले सभी लोगों को अब यह समझना होगा कि चीन ने ऐसी स्थिति कैसे बना ली है कि वह किसी भी देश को नियन्त्रित कर सकता है। इसका जबाब निश्चित रूप से स्थानीय विनिर्माण बढ़ाना है खासतर पर सभी महत्वपूर्ण चीजों का और यह निश्चित रूप से हैरानी की बात होगी।

करीब 40 साल पहले, अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रमुख अधिकारी उस्खा, मुक्त-बाजार एवं बिद्दारों का बहुत नियमण था जिसमें खुली

प्रतिस्पर्धा, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, कम शुल्क बाधाएं और विनियोग उदारीकरण जैसे पहलू शामिल थे। इसके कारण सरकार की योजनाओं पर मुक्त बाजार विचारधारा की नियांयक बढ़त देखी गई। खैर, अब यह सोच पूरी तरह से बदल गई है। टैरिफ बाधाएं बढ़ गई हैं और सरकारी उद्यमों को समर्थन दिया जिन्होंने सरकारी खजाने को खाली कर दिया।

ऐसे में सबल यह है कि फिर औद्योगिक नीति और इसके मुख्य घटक, विनिर्माण को अब बृद्धि के संदर्भ में क्यों तरजीह दी जा रही है? इसका जबाब नहीं है चीन। क्या आपने यह नहीं देखा कि कैसे सोची-समझी औद्योगिक नीतियां किसी देश को बदल सकती हैं जैसे विश्व युद्ध से पहले जापान और बाद में ताइवान और दक्षिण देशों के बाद विद्युत बढ़ाना भी है? अमेरिका के राष्ट्र-पूर्णता डॉनल ट्रॉप, स्टील से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और दबाओं तक का विनिर्माण अपने देश में करना चाहते हैं। इसके पूर्ववर्ती राष्ट्र-पूर्ण जो बाइडन ने सेकंड डब्टर और हरित प्रौद्योगिकों के लिए भारी समिस्टी दी थी। ब्रिटेन नियमाताओं के ऊंची बिलों पर सम्बिस्डी देने पर विचार कर रहा है वहां भारत ने 17 क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्तों को देखा कि कैसे देखी गई है।

इंडियानियों के ऊंची बिलों के ऊंची बिलों को खाली कर दिया है, जिसमें खुली

प्रतिस्पर्धा, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, कम शुल्क बाधाएं और विनियोग उदारीकरण जैसे पहलू शामिल थे। इसके कारण सरकार की योजनाओं पर मुक्त बाजार विचारधारा की नियांयक बढ़त देखी गई। अब यह नियमण को अब बृद्धि के संदर्भ में क्यों तरजीह दी जा रही है? इसका जबाब है चीन। क्या आपने यह नहीं देखा कि कैसे सोची-समझी औद्योगिक नीतियां किसी देश को बदल सकती हैं जैसे विश्व युद्ध से पहले जापान और बाद में ताइवान और दक्षिण देशों के बाद विद्युत बढ़ाना भी है? अगर औद्योगिक नीति और इसके मुख्य घटक, विनिर्माण को अब बृद्धि के संदर्भ में क्यों तरजीह दी जा रही है? इसका जबाब है चीन। क्या आपने यह नहीं देखा कि कैसे सोची-समझी औद्योगिक नीतियां किसी देश को बदल सकती हैं जैसे विश्व युद्ध से पहले जापान और बाद में ताइवान और दक्षिण देशों के बाद विद्युत बढ़ाना भी है? अगर औद्योगिक नीति और इसके मुख्य घटक, विनिर्माण को अब बृद्धि के संदर्भ में क्यों तरजीह दी जा रही है? इसका जबाब है चीन। क्या आपने यह नहीं देखा कि कैसे सोची-समझी औद्योगिक नीतियां किसी देश को बदल सकती हैं जैसे विश्व युद्ध से पहले जापान और बाद में ताइवान और दक्षिण देशों के बाद विद्युत बढ़ाना भी है? अगर औद्योगिक नीति और इसके मुख्य घटक, विनिर्माण को अब बृद्धि के संदर्भ में क्यों तरजीह दी जा रही है? इसका जबाब है चीन। क्या आपने यह नहीं देखा कि कैसे सोची-समझी औद्योगिक नीतियां किसी देश को बदल सकती हैं जैसे विश्व युद्ध से पहले जापान और बाद में ताइवान और दक्षिण देशों के बाद विद्युत बढ़ाना भी है? अगर औद्योगिक नीति और इसके मुख्य घटक, विनिर्माण को अब बृद्धि के संदर्भ में क्यों तरजीह दी जा रही है? इसका जबाब है चीन। क्या आपने यह नहीं देखा कि कैसे सोची-समझी औद्योगिक नीतियां किसी देश को बदल सकती हैं जैसे विश्व युद्ध से पहले जापान और बाद में ताइवान और दक्षिण देशों के बाद विद्युत बढ़ाना भी है? अगर औद्योगिक नीति और इसके मुख्य घटक, विनिर्माण को अब बृद्धि के संदर्भ में क्यों तरजीह दी जा रही है? इसका जबाब है चीन। क्या आपने यह नहीं देखा कि कैसे सोची-समझी औद्योगिक नीतियां किसी देश को बदल सकती हैं जैसे विश्व युद्ध से पहले जापान और बाद में ताइवान और दक्षिण देशों के बाद विद्युत बढ़ाना भी है? अगर औद्योगिक नीति और इसके मुख्य घटक, विनिर्माण को अब बृद्धि के संदर्भ में क्यों तरजीह दी जा रही है? इसका जबाब है चीन। क्या आपने यह नहीं देखा कि कैसे सोची-समझी औद्योगिक नीतियां किसी देश को बदल सकती हैं जैसे विश्व युद्ध से पहले जापान और बाद में ताइवान और दक्षिण देशों के बाद विद्युत बढ़ाना भी है? अगर औद्योगिक नीति और इसके मुख्य घटक, विनिर्माण को अब बृद्धि के संदर्भ में क्यों तरजीह दी जा रही है? इसका जबाब है चीन। क्या आपने यह नहीं देखा कि कैसे सोची-समझी औद्योगिक नीतियां किसी देश को बदल सकती हैं जैसे विश्व यु

